web: www.nyaysakshi.com ‖ पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल ‖ पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 08 मार्च 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 160

कार्यान्वयन के लिहाज से भी नीति अच्छी हो:नायडू

» सरकारी कार्यक्रमों की डिलिवरी में सुधार का आह्वान

हैदराबाद (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने आज कहा कि भारत में नीति निर्माण में कोई कमी नहीं है लेकिन अधिक महत्वपूर्ण इन नीतियों का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन है। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन के लिहाज से भी नीति अच्छी होनी चाहिए।

आज हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) के संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति ने विकास के लिए समावेशी और टिकाऊ दृष्टिकोण का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों का लाभ अंत्योदय की सच्ची भावना से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जैसा कि महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान नेताओं ने सोचा था। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र पीछे नहीं रह जाना चाहिए।

सरकारी कार्यक्रमों में लोगों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए नायडू ने कहा कि भारत जैसे बड़े आकार का देश शासन में लोगों की भागीदारी के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। उन्होंने सेवा वितरण में सुधार और भ्रष्टाचार कम करने के लिए डिजिटल तकनीकों का अधिकतम उपयोग करने का भी आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि शासन में सुधार के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने और प्रशासन में परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए प्रशासकों की मदद करनी चाहिए।

प्रशासन से जुड़े हर पहलू में परिवर्तन पर ध्यान आकर्षित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान समय में प्रशासन केवल कार्यान्वयन तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें प्रबंधन और शासन की व्यापक अवधारणा समाहित है। उन्होंने सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं को लागू करने और शासन में एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।

देश में सिविल सेवकों, प्रबंधकों और प्रशासकों के क्षमता विकास में प्रमुख संस्थानों में से एक के रूप में उभरने के लिए एएससीआई की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसके संकाय को प्रशासकों के बीच व्यवहार और मानसिकता में बदलाव लाने की दिशा में काम करने को कहा है। नायडू ने एएससीआई के संकाय सदस्यों से कहा कि आप से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक अधिकारी नागरिक-केंद्रित और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाएंगे जो समय की मांग है।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए दुनिया के कई देश भारत की ओर देख रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि एएससीआई अपने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, सार्वजनिक नीति में विशेषज्ञता और परामर्श सेवाओं के बल पर सरकारों, कॉरपोरेट्स और दूसरे देशों को भी सही तरह से मदद कर सकता है।

सार्वजनिक-निजी-भागीदारी को समय की मांग बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लिए विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने नीति निर्धारकों, प्रशासकों और सलाहकारों को नियमित सरकारी कार्यों के अलावा पीपीपी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। एएससीआई की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने इसके परिसर में घूमकर प्रशिक्षुओं से बातचीत की। उन्होंने एएससीआई के परिसर में एक पौधा भी लगाया। एएससीआई देश का सबसे पुराना प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है।

बीजद ने घोषित किये चार उम्मीदवार

» राज्यसभा चुनाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल (बीजद) प्रमुख नवीन पटनायक ने राज्यभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है। पटनायक ने भुवनेश्वर में शनिवार को कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए सुभाष सिंह, मुन्ना खान, सुजीत कुमार और ममता महंत बीजू जनता दल के उम्मीदवार होंगे।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यसभा की चार सीटों पर चुनाव के लिए बीजद उम्मीदवारों के नामों की शनिवार को घोषणा की। ये सीटें अगले महीने से खालीहो रही हैं। बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष पटनायक ने राज्यसभा चुनावों के लिए सुभाष सिंह, मुन्ना खान, सुजीत कुमार और ममता महंत को नामांकित किया। ओडिशा की 10 में से चार राज्यसभा सीटें दो अप्रैल को रिक्त होंगी। ओडिशा से राज्यसभा सदस्य बीजद के अनुभव मोहंती, नरेंद्र कुमार स्वैन और सरोजिनी हेम्ब्रम तथा कांग्रेस के रंजीब बिस्वाल के कार्यकाल के पूर्ण होने से ये सीटे खाली होंगी।

सिंह ने ओडिशा बिल्डिंग एंड अदर कंसट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेयर बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जनता दल के पूर्व नेता खान अल्पसंख्यक मामलों के विभाग में सलाहकार थे जबकि कुमार विशेष विकास परिषद के सलाहकार थे। महंत मयूरभंज जिले से बीजद महिला शाखा की सदस्य हैं। बीजद ने पिछले साल राज्यसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार अश्विनी वैष्णव का समर्थन किया था।

केन्द्र सरकार ने दो चैनलों पर लगा प्रतिबंध हटाया

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने शनिवार को दो मलयाली भाषा के समाचार चैनल एशियानेट समाचार और मीडियावन के प्रसारण पर शुक्रवार को लगाई रोक को हटा लिया गया। सूत्रों ने बताया कि देशभर में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के चलते दोनों समाचार चैनलों के प्रसारण पर शुक्रवार को 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे आज सुबह हटा लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मलयालम समाचार चैनलों एशियानेट समाचार और मीडियावन को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा को गलत तरीके से प्रसारित करने के लिए शुक्रवार को अगले 48 घंटे तक प्रसारण पर रोक लगायी थी। मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में कहा कि टेलीविजनों के प्रसारण के सम्बंध में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर ये खबरें दिखाई गईं थी। इसमें एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल के हमले की बात कही गयी जिससे समाज मे अशांति फैल सकती थी। मंत्रालय ने शुक्रवार को साढ़े सात से लेकर रविवार शाम साढ़े सात बजे तक 48 घंटे के लिए मीडिया वन और एशियानेट न्यूज़ के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

» अभी 200 यूनिट फ्री है इलेक्ट्रिसिटी

अब दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ना तय

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने आगामी वित्तीय वर्ष में नई बिजली दरें तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। होली के बाद 18 मार्च को इसे लेकर जनसुनवाई का आयोजन किया है। उपभोक्ताओं से जनसुनवाई में शामिल होने के साथ उनके सुझाव भेजने के लिए 20 मार्च तक का समय भी दिया है। जनसुनवाई और बिजली वितरण कंपनियों के लेखा जोखा का आकलन करने के बाद ही बिजली की नई दरें तय की जाएगी।

डीईआरसी की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में बिजली कंपनियों के साथ इसके सभी पक्षों को जनसुनवाई शामिल होने की अपील की है। बिजली वितरण

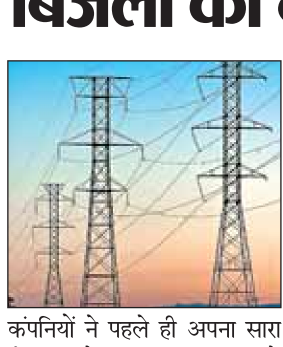

कंपनियों ने पहले ही अपना सारा लेखा जोखा डीईआरसी को उपलब्ध करा चुकी है। जिसमें बिजली वितरण कंपनियों की राजस्व रिपोर्ट शामिल है। उसमें बिजली खरीदने से लेकर उसके वितरण और राजस्व की पूरी जानकारी है। सभी कंपनियों की यह रिपोर्ट डीईआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली सरकार का दावा है कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में उपलब्ध है। वर्तमान में दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। उसके बाद 400 यूनिट तक कुल बिल पर 50 फीसदी की सब्सिडी सरकार देती है।

उसके बाद अलग-अलग श्रेणी में अलग-अलग दरें है। सूत्रों की माने तो इस बार बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी करने के बजाएं फिक्स चार्जेज में मामूली बढ़ोत्तरी की जा सकती है। अभी 20 रूपये प्रति किलोवाट चार्ज लिया जाता है। 2019 में फिक्स चार्ज कम किया गया था। जबकि 2018 में 2 किलोवाट के लोड वाले बिजली कनेक्शन पर फिक्स चार्ड 125 रूपये देना होता था। सरकार इस बार सब्सिडी तो जारी रख सकती है मगर फिक्स चार्ज में मामूली बढ़ोत्तरी कर सकती है।

स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर भिड़ंत में 11 की मौत

मुजफ्फरपुर (आरएनएस)। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं।

हादसा मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में हुआ। यहां पर एक स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उतर गए। स्कॉर्पियो एनएच-28 पर जा रही थी, तभी ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, अभी

मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को एंबुलेंस में रखकर श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया है। मरने वाले सारे लोग मुजफ्फरपुर के हथौड़ी के रहने वाले थे। पुलिस फिलहाल जेसीबी मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त हुए ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो को हटाने का काम कर रही है, ताकि रोड पर लगे जाम को हटाया जा सके। पुलिस ने घटना की जांच भी शुरू कर दी है।

पुलिस ने कहा कि हादसा शनिवार तड़के हुआ है। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि इस दुर्घटना में जो स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है वह उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तर प्रदेश का था। घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी है। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है।

बंद के समर्थन पर किसी संगठन को विदेशी फंड लेने से नहीं रोक सकते:सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) 2010 का इस्तेमाल करते हुए गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की विदेशी फंडिंग रोक दिया है।

केंद्र सरकार के इस कदम को एनजीओ इंसाफ (इंडिया सोशल एक्शन फोरम) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते

हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सुनवाई की। दो सदस्यीय बेंच ने शुक्रवार को अपने फैसले में केंद्र को झटका दिया। सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई संगठन सक्रिय राजनीति में नहीं है और जनहित के लिए बंद या हड़ताल का समर्थन करता है, तो उसे राजनीतिक संगठन घोषित कर विदेशी फंड प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसी संगठन को विदेशी धन प्राप्त करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को एफसीआरए के नियमों और प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि श्प्रावधानों से स्पष्ट है कि बंद, हड़ताल, रास्ता रोको इत्यादि को राजनीतिक कार्रवाई के सामान्य तरीके के रूप में लिया जाता है, कोई भी संगठन जो बिना किसी राजनीतिक लक्ष्य के अपने अधिकारों के लिए धरना-प्रदर्शन करने वाले लोगों का समर्थन करता है, तो उसे राजनीतिक प्रवृति का संगठन घोषित कर दंडित नहीं किया जा सकता।

जब पीएम मोदी महिला की बात सुनकर हुए भावुक

» महिला ने मोदी की भगवान से की तुलना

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे जनऔषधि दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और इस

दौरान उन्होंने इसका लाभ पाने वाले लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान एक महिला से बातचीत के दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए कहा कि देशभर में 6200 जन औषधि केंद्रों ने दो हजार से ढाई हजार करोड़ रुपये की बचत करने में लोगों की मदद की है। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने चिकित्सकों से जेनेरिक दवाएं लिखने को कहें और प्रत्येक माह, एक करोड़ से अधिक परिवार जन औषधि केंद्रों से दवाएं ले रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना का लाभ पाने वाले दीपा शाह ने पीएम मोदी से बात करते हुए रोने लगी। दीपा शाह ने कहा कि 2011 में मुझे पैरालाइज हुआ था और वह बोल नहीं पाती थी। जब मेरा इलाज चलता था तो मेरी दवाइयां बहुत महंगी आती थी। फिर आपकी जनऔषधि दवाई मिली और उन्हें खाना शुरू किया।

होली के बाद बनेगी भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम

नईदिल्ली (आरएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा होली के बाद कर सकते हैं। यह जानकारी हाल ही में पार्टी सूत्रों से मिली है। अमित शाह की पुरानी टीम से नड्डा की नई टीम कितनी अलग होगी, किन नए चेहरों को इसमें मौका मिलेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

वैसे तो फरवरी के आखिरी सप्ताह में ही नई टीम के गठन की संभावना थी। लेकिन नड्डा के अपने बेटे की शादी समारोह व कुछ अन्य व्यस्तताओं के चलते नई टीम का गठने नहीं हो सका। पार्टी सूत्रों का कहना है कि,10 मार्च को होली बीतने के बाद नड्डा राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर सकते हैं। जेपी नड्डा 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। अमूमन हर राष्ट्रीय

अध्यक्ष संगठन के संचालन में अपनी सुविधा के लिए नई राष्ट्रीय टीम बनाता है। इस फेरबदल के क्रम में जहां राष्ट्रीय टीम में पहले से मौजूद कुछ सदस्यों की जिम्मेदारियां बदलतीं हैं, वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जाता है।

आने वाले समय में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत सात से नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि नड्डा एक रणनीति के तहत इन राज्यों के कुछ नए चेहरों को राष्ट्रीय टीम में मौका दे सकते हैं। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कोटे से राष्ट्रीय टीम में तीन पद पहले से ही खाली हैं। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने से पहले तक श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह, पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे। इस प्रकार श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ के स्थान पर यूपी से दो चेहरों को जगह मिलना तय माना जा रहा।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम की घोषणा हो जानी चाहिए थी। मगर कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो सका है। लिहाजा अब मार्च में नई राष्ट्रीय टीम घोषित हो जाने की संभावना है। हो सकता है कि होली बीतने के कुछ ही दिनों में नई टीम के सदस्यों की सूची जारी हो जाए।

कच्चे तेल की कीमतों में आई 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट

» अब भारत में 4 रुपये तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल

नई दिल्ली (आरएनएस)। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बीते शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में 10 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल के भाव में यह गिरावट ओपीईसी देशों द्वारा प्रोडक्शन में कटौती नहीं करने के फैसले के बाद देखने को मिली। इसीलिए एक्सपट्र्स मान रहे है कि भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम आने वाले महीनों में 4 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकते है।

सूत्रों के अनुसार यह गिरावट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों की वजह से आई है। मसलन यूएस डब्ल्यूटीआर और ब्रेंट क्रुड तेल के भाव में गिरावट आई। दोनों कच्चे तेल के भाव में क्रमशरू 10.07 फीसदी और 9.4

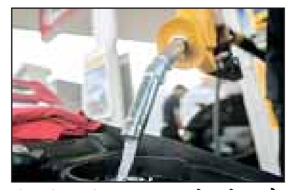

फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में इस कटौती का सीधा लाभ घरेलू बाजार में भी देखने को मिलेगा। इस साल अब तक पेट्रोल के दाम में 4 रुपये प्रति लीटर की कटौती हो चुकी है। वहीं डीजल के भाव की बात करें तो साल की शुरुआत से लेकर अब तक 4.15 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती हुई है। गौरतलब है साल 2008 में सबसे बड़ी कटौती की गई थी।

महत्वपूर्ण एवं खास

संसद भवन के गेट पर कारतूस लेकर पहुंचा शख्स, हुआ हंगामा

नईदिल्ली (आरएनएस)। संसद भवन में एक सांसद से मिलने यहां पहुंचा एक व्यक्ति उस वक्त तमाशा बन बैठा जब वह संसद भवन के द्वार पर गलती से जेब में कारतूस लेकर चला गया। हालांकि, इससे कुछ हुआ तो नहीं, मगर गैर-जिम्मेदार शख्स ने खुद का तमाशा जरूर बना लिया। घटना गुरुवार दोपहर बाद के वक्त की बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक अफरा-तफरी मचवाने वाले शख्स का नाम अख्तर खान (44) है। उसकी जेब से 0.32 बोर के कारसूत मिले। पूछताछ में पता चला कि अख्तर को एक सांसद ने मिलने के लिए संसद भवन बुलाया था। धोखे से और जल्दबाजी में वो जेब में पड़े कारतूस निकाल कर रखना भूल गया। पुलिस और अन्य एजेंसियों ने पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया।

शाहरुख द्वारा इस्तेमाल अवैध पिस्तौल जब्त!

नईदिल्ली (आरएनएस)। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में 24-25 फरवरी को भड़की हिंसा के बीच हवलदार दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान से पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। सूत्र बताते हैं कि पुलिस रिमांड में चल रहे शाहरुख की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच एसआईटी ने शुक्रवार को घटना में शाहरुख द्वारा इस्तेमाल अवैध पिस्तौल जब्त कर ली! हालांकि, दिल्ली पुलिस प्रवक्ता से लेकर क्राइम ब्रांच और उसकी एसआईटी के किसी अधिकारी ने शुक्रवार रात बारह बजे तक इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी मीडिया को नहीं दी थी। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक, पिस्तौल तो शुक्रवार को मिल गई, लेकिन घटना वाले दिन शाहरुख के पास मौजूद 1-2 जीवित कारतूस अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि, पुलिस को घटनास्थल से शाहरुख के हथियार से चलाए गए कारतूसों के खोखों के मिलने की बात पहले ही सामने आ चुकी है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने अधिकृत रूप से शुक्रवार देर रात हिंसा में अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या बताई। एफआईआर के बाबत भी ब्यौरा दिया।

गिरफ्तार पार्षद के कई रिश्तेदार एसआईटी की नजर में

नईदिल्ली (आरएनएस)। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर एसआईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। सात दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहे ताहिर हुसैन की घटना वाले दिन की कुंडली खंगालने पर शुक्रवार को मामले की जांच कर रही एसआईटी को काफी कुछ जानकारियां हासिल हुई हैं। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के एक सूत्र के अनुसार, घटना वाले दिन ताहिर हुसैन ने सबसे ज्यादा और लगातार जिन लोगों के साथ बात की थी, एसआईटी ने शुक्रवार को उन 15 लोगों की पहचान कर ली। यह बातचीत मोबाइल के जरिए हुई। ताहिर ने इन सबसे उसी दिन इतनी ज्यादा देर तक क्यों और क्या लंबी बातचीत की? इसका खुलासा नहीं हो सका है।

सीरिया में संघर्ष विराम पर अमेरिका का इनकार

संयुक्त राष्ट्र। अमेरिका ने सीरिया में संघर्ष विराम को लेकर रूस और तुर्की के बीच हुए समझौते का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। राजनयिकों ने बंद कमरे में हुई बैठक के बाद यह जानकारी दी। राजनयिकों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वैसिली नेबेन्जिया ने सुरक्षा परिषद के 14 अन्य सदस्य देशों से संयुक्त बयान का समर्थन करने का आग्रह किया था, जिसे अमेरिका ने असामयिक करार देते हुए शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया।नेबेन्जिया ने कहा, विभिन्न देशों ने समझौते पर ध्यान देते हुए इसका स्वागत किया। लेकिन एक प्रतिनिधिमंडल के रुख के चलते इसे स्वीकार नहीं किया जा सका। गौरतलब है कि तुर्की और रूस के बीच सहमति के बाद उत्तरी सीरिया में शुक्रवार से संघर्ष विराम लागू किया गया था।